



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31 1990/माघ 11, 1911

No. 22] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1990/MAGHA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य संचालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 198—आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1990

विषय:—1989-90 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई
505.501 मिलियन (505.501,000) येन ऋण सहायता)
की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

फाइल सं. आई पी सी/23(28)/85—88—1989-90 के लिए
505.501 मिलियन येन (505.501,000) (ऋण सहायता) की
जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध
में लागू होने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी
गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

तेजेंद्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 198—आई टी सी
(पी एन)/88—91, दिनांक 31-1-90 का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए (1989-90 के लिए
येन 505.501 मिलियन (येन 505.501,000) (ऋण सहायता) की
जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध
में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1—सामान्य शर्तें :

1. (1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 505.501
मिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ. ई. सी. डी.
और विकासशील देशों के हक में मंगठिन की गई है। तदनुसार, इस ऋण
के अधीन अधिप्राप्त होने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक
सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की
जा सकती हैं। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।
इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मध्ये आयात की जा सकती हैं
उनकी सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1989-90 के लिए येन 505.501
मिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय
प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे. एन." होगा। ये प्रत्यय मुख्य

नियंत्रक, आयात-निर्वाह के लिए आयात लाइसेंस के अग्रणी पत्र में भी उल्लेख जाएंगे।

1(3) बैंक खाते, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमिशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-सीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैधता अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो हर मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पहले आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टो. सी.) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पहले आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए उन क्रय आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत, समर्पित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत, हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और/या भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्विकार्य नहीं हैं।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समाप्ता जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा-उल्लिखित पहले आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत-खदान के लिए आखिरी तिथि निम्नित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1991 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू. एस. डालर या पीण्ड स्टैलिम में एक येन, एक सेंट या एक पेनी के कम की मात्रा के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमिशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यंत निशुल्क लागत-सीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की

जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े या खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर भर्पाई बैंक अफ डंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतखदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अग्रणी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3—संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए

3(1) 1989-90 के लिए येन 505,501 बिलियन के अनुदान सहायता से संबंधित इस संविदा की व्यवस्था 9-10-89 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है जो भारत सरकार के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगी।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1989-90 के लिए जापान अनुदान सहायता के अधीन बैंक अफ डंडिया, टोकियो के नाम से सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जनपथ भवन, जेनेपथ नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतखदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्गों के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) जैसे की आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत, हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्रपार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-3 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टो. सी.), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक संशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए लागू होगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में

उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को महायत्ना लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद महायत्ना लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001 बैंक आफ इण्डिया टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और महायत्ना लेखा एवं लेखा परीक्षा, नियंत्रक की सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक की प्रवृत्ति कराएगा।

4(5) पीतलवान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो की प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निविष्ट धनराशि को रिडीज करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चें, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन सरकारी विभागों के मामले में, भारतीय दूतावास टोकियो बी. ओ. आई., टोकियो को बैंकिंग प्रसारों का भुगतान करेगा और फिर संबद्ध विभाग के नामे खाला जाएगा।

खण्ड-5--रपया जमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनियम पीत परिवर्तित दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 के 'ग' में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात की सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को भुकाई गई येन (यूएस डालर) पीण्ड स्टॉलिंग धनराशि के बराबर रपया उन माघकों में जहाँ येन योग्य है ब्याज के खर्चें सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर विदेशी, संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रपया जमा करने की तिथि तक ही अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब, लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन) 83, दिनांक 10-8-83 और स. 35-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रपया जमा किया जाता है के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येन यू. एस. डालर/पीण्ड धनराशि के बराबर रपया की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 113-आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-89 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी

या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिभूजित की जाएगी। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधि-भूजित कर दिया जाएगा। इस बात की सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात-दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही येन धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि अन्तःप्रारण परिस्थितियों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से मूल पीत-परिवर्तित दस्तावेजों के बिना माल का विवरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे में गीत जमा करा दी गई है। जिस लेखा पोथी में उपर्युक्त रपया जमा करना चाहिए वह है डिपोजिट एण्ड एक्वालिज 8443-डिविज डिपोजिट-- डिपोजिट्स फोर परफेजिंग एटस्कड्रा एक्वाड परफेज ग्रान्ट ऐंड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1989-90 येन 505.501 बिलियन ग्रान्ट ऐंड (ऋण सहायता)।

5(2) उल्लिखित धनराशि जालान के दाहिने ओर कॉड सं. 5130000009 वसति हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस जारी, दिल्ली में सरकार की साथ में मकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उप-संस्था किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस जारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्राप्त) की सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 114-आई टी सी (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-89 में यथा-निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन-प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐनो मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक की ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। जालान के विभिन्न कालों में करते समय आयातकों/उनके बैंकों की इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सम्पूर्ण सूचना निरपवाद रूप से भेज दी गई है। खजाना जालान में निम्नलिखित ब्याज निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :-

- (क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. और दिनांक
- (ख) येन मुद्रा को वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि-अर्जन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) भुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए गिना जाएगा।
- (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जागी है लेकिन सरकारी विभागों द्वारा कोई ब्याज देय नहीं)।

उसके पश्चात् सी. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का सन्दर्भ देते हुए और वीजक सहा पीत परिवर्तित दस्तावेजों को संभरक करते हुए खजाना जालान रपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:-भारत के आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रपया का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अवश्य

की मूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दम बिलों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाव सी. ए. ए. एण्ड ए., बिस्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति धर रूपया निवेशों का धनराशि की पुष्टीकरण करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड-6 विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट:—

**आयातक को सम्मरक को भेदा किए गए भुगतान की राशि और तिथि का पता करने के लिए भलग से व्यवस्था करनी चाहिए। आयातक के ऋणदाता द्वारा पोत परिवहन धादि वस्तावेजों की बाद में या देरी से प्राप्ति को रूपया निक्षेप पर वेय ब्याज की धागिक या पूरी धनराशि को माफ करने के लिए वहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6(2) संभरकों को विषय शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस का उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टेलिफो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी जानेवाली शर्त साफ-साफ भुगतान के नियमन के अधीन अनुबंध-1 में बर्गई जानी चाहिए। विवाद से निपटने की शर्तें ठेके की शर्त में शामिल होनी चाहिए।

6(4) मधिय्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1989-90 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभाओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंधों की सूची:—

अनुबंध 1 पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबंध 2 पात्र पथ्य वस्तुओं की सूची

**आयातक को पोतलदान और उसके मद्देभुगतान और बकाया रह गई राशि से सम्बन्धित एक मासिक रिपोर्ट प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, बिस्त मंत्रालय, जनपथ भवन, 5वीं मंजिल, बी बिग, जनपथ, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

अनुबंध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए प्राबिदन करने का प्रपत्र

अनुबंध 4

भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी जी देश

आस्ट्रेलिया

कनाडा

फिनलैंड

जर्मनी संघीय गणराज्य

आइसलैंड आयरलैंड

जापान

वी भीयरलैंड

नाब

स्पेन

स्वीटजरलैंड

दि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स

बेल्जियम

डेनमार्क

फ्रान्स

यूनाइ

इटली

लग्जमबर्ग

न्यूजीलैंड

पुर्तगाल

स्वीडन

सुर्फी

(ख) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

अ(1) नाम-ओ पी. ई. सी. विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र

तुमोशिया

मोरक्को

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बुरुंडी

केप वर्डी द्वीप समूह

चाड

कांगो, वमोह गणराज्य (1)

इथोपिया

थाना

गुयाना

बोत्सवाना

केमरु

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र

कमोरो द्वीप समूह

क्वेटोरियल गाईना

आम्बिया

(1) वमोह गणराज्य का नाम वमोह गणराज्य है।

2. सेंट हेलेना और जेप (2)

सी टोम प्रिन्सिपि
ब्राइरी कोस्ट
कैम्या
लिसोवे
लाइबेरिया
मालागासी गणतन्त्र
मनाबी
मारिटेनिया
मारोशस
मोजाम्बिक
साइर
पुर्तगाल गिनी
रि-यूनियन
रोडेगिया

बाला

सेनेगाल
सिचिलीज
मियरा लिमोन
सोमालिया
सूडान
स्वीडिश
टोरो अफास और हम्मास
टोंगो
युगाण्डा
तंजानिया, गणतन्त्र संघ
अपर वोल्टा
आयरे गणतन्त्र
कंबिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतन्त्र
एल साल्वाडोर
गुआडालोपा
ग्वाटेमाला
हीती
होन्डुरस
जमैका
मार्टिनिक्क
मक्सिको
नीदरलैंड एंटीलीज
बेल्जिज (बा.) एन. आई. ई

(2) निम्नलिखित द्वीप सहित असेम्बल, डिस्टन डाउन इन्सोसवल्स,
नाइटिडोन, गफा ।

(3) ऐन समूह, अरबा, बोनाहरे, कयारा कायो, सहा, सेंट दूस्टासिट, सेंट
मारटिन (दक्षिणी भाग)

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) दक्षिण राज्य (2)

निकारागुआ

पनामा

सेंट लूयरी और मिडवूलांन

ट्रिनिडाड टाबागो

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेंटीना

बोलिविया

ब्राजील

चिली

कोलम्बिया

फ्रांस्कोइ द्वीप समूह

क्रामिरी गिरी

गुयाना

पराग्वे

पेरु

सूरिनाम

उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन

इजराइल

जोर्डन

लेबनान

ओमान

सिरियाई अरब गणतन्त्र

यूनाइटेड अरब एमिरात (3)

यमन अरब गणतन्त्र

यमन जनवादी डी. आर. (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान

बांगला देश

भूटान

बर्मा

मालदीव

नेपाल

पाकिस्तान

श्री लंका

7. सुदूर पूर्व एशिया

बुर्नेई

हांगकांग

हेमर गणतन्त्र

लाओस का कारिया गणतन्त्र

मकाओ

(1) मूक्य द्वीप एन्टिगुआ, टोमिनिका, ग्रनेडा, सेंट किट्स (सेण्ट करिस्टेके)
नेविन ग्रैगुइला, सेंट लूगिया और सेंट विलेफ्रेड ।

(2) मेन चार्डल, मास्सेसे रेंट, येमान, सुकी और काइकोस और ब्रिटिश
वरजिन द्वीप समूह ।

(3) फ्राईजुमन, कुवई, फजाइर, शस घल खेमाह जरेजाह और उम्मस
कवेवन ।

(4) अरब और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित ।

मलेसिया
फिलीपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाईलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

अनुबन्ध—2

पञ्च पथ्य वस्तुओं की सूची

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
किरी
गिल गिल्बर्ट और एलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
माइक्रो
न्यू कैलेडोनिया
हिड्यू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य यू. एम.) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (हि.)
टोसो
न्यूफ़ाउन्डलैंड (प्र. और प्र.)
बालिस और कर्ना
पश्चिम समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
टुर्की
यूगोस्लाविया

खण्ड 2 प्रो. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोस्निया
लीबियाई अरब गणतंत्र
रोमान
माल्डीविया
इक्वडोर
बेल्लुएला
ईरान
ईराक
कुवेत
कातार
सऊदी अरब
इथियोपिया
आबु धाबी

(5) सोलावदी, फ्राईलैंड समूह (ताहिती सहित) की शामिल करते हुए, अस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोटु, ऑक्सीडेंट ग्रुप और मार्कोस द्वीप समूह ।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का दूरस्थ प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (गान को छोड़कर) ।

1. रोज
2. विशेष इस्पात और मिश्र धातु इस्पात सहित इस्पात
3. टुकड़ों और ट्रेक्टरों इसके व्यापारिक ब्लीकल और टूट्टील के निर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे ।
4. रसायन
5. जापान अनुदान परियायना और भारत जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे संघटक, और कच्चा माल ।
6. बिजली के टुकड़ों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे ।
7. मशानरी, संघटक, संयोजन, अतिरिक्त पुर्जे और कच्चा माल ।
8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशानरी और उपस्कर ।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे ।
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें, जिन पर आपम में सहमति हो ।

अनुबन्ध—3

‘भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र’

मं.

दिनांक :

सेवा में

सहायता लेखा नया लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, प्राथमिक कार्य विभाग,
यू. सी. प्रो. बैंक बिल्डिंग,
प्रथम मंजिल, पामियामन्ट स्ट्रीट,
नई दिल्ली 110001

विषय—1989-90 के लिए येन 503.501 बिलियन आपानी ऋण
अनुदान महायन्त्रायेन के अधीन आपान से आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन आपान से जो कि आपान के संबंध में हे संबंध संभरक के साम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों प्रस्तुत करने हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और यह तारांक जिस तक बंध है ।
- (ग) प्राप्ति के तरीके क्या यह सीधे श्रय या औपचारिक ऋण अन्त-राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेत होना चाहिए कि क्या संबंध का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।
- (ङ) माल का उद्गम देश ।
- (च) संबंध का कुल लागत भाग मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाला भारतीय एंशेंट के कमीशन की धनराशि ।

- (अ) वह कुल सभा तथा भाग मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) संभरकों के मूल्य की गयी संविदा की संख्या और दिनांक
- (ञ) संभरक का नाम और पता
- (ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित निधि जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।
- (ठ) संपूर्ण की पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि
- (ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान विस्तारित हुए।
- (क) पोतलदान अनुबंध (वाहनान्तरण पार्से/शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निश्चित की जाए।
- (ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (त) क्या अभी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई हैं। यदि हां, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य।
- (थ) वह भारतीय पतन अर्थात् उपकरण/माल का पोतलदान किया जाना है।

भारतीय,

सन्बन्ध- 4

संख्या

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—येन 505.501 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अर्थात् आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के पास दिनांक ----- की किए गए करार के नियम और शर्तों के अनुसार आपको पत्रद्वारा संसर्ग ----- का (परिशिष्ट में दिए गए बयानों के अनुसार) येन तक की धनराशि की भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के साथ संभरकों की सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठीकृत की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने के बाद, आपको ----- (आयातक के बैंक का नाम और पता) की सभी मूल पत्र परिवहन दस्तावेजों (परक्राम्य) और उसके साथ-साथ दस्तावेजों के प्रतिरूपित पूरे सेट और यदि कोई तत्क्षण भुगतान किया गया हो तो उसके सहित संभरक की किए गए भुगतान के ऋण बीजक की एक प्रति भेजनी चाहिए।

3. आयातक द्वारा दस्तावेजों के भेजने प्राप्ति के लिए भाड़ों सहित भरा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े भारतीय दूतावास टोकियो/आयातक बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तथापि भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा ई. ओ. आई की सरकारी विभागों से संबद्ध बैंकिंग भाड़ों का भुगतान किया जाएगा और सम्बंधित विभाग के नामे डाला जाएगा।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र ----- तक वैध रहेगा।

9. कृपया संविदा से संबंधित सभी पत्राचार में और भुगतान वर्णन के साथ बीजक में भी भुगतान के लिए इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या की कोट करें।

भारतीय,

लेखा अधिकारी

प्रति प्रेषित है:—

1. आयातक ----- की उनके पत्र सं. ----- दिनांक ----- के संदर्भ में

(1) यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अर्थात् आयातों की नियंत्रित करने वाली संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अधीन जारी किया जाता है। लाइसेंसिंग शर्तों और संबद्ध सार्वजनिक सूचना/और आदेशों आदि का अवलोकन किया जाए और संबंधित आयात/विदेशी भुगतान के लिए समुचित कार्रवाई की जाए।

2. आयातक का बैंक ----- उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को 1/4 येन/ए एस डालर/पीएड के बराबर रुपये जमा करने का व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को जुर्माना दी गई धनराशि के रूप में गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेख में लुप्य रूपमा जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और 35/आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेख में जमा कराना होगा ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसकी सरकारी लेख में रूपमा निक्षेप किया जाता है। (इस वर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल मंड दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है तथापि सरकारी विभागों द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।

3. येन धनराशियां बालान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुपंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (प्रादेशिकी और आवाता) के नाम में और उसकी वेब दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 113 टी सी आई (पी एन)/88-91 दिनांक 6-4-89 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर ध्यान दिया जाना है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांस 8443 मिश्रित डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परवैजिस एटमैक्चुर एक्साइज—परवैजिस प्राइड ऐड काम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1989-90 (येन 505.501 मिलियन ग्रांट एण्ड डेबिट गिलीज)।

4. जिस मामले में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें बालान की मूल रूप में एक प्रतिस्ति बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रत्येक पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
जनपथ भवन, बी बिल्डिंग, 3वीं मंजिल,
जनपथ, नई दिल्ली-110001.

5. जिस मामले में मुख्य रूप से समकालीन पर जारी की गई सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित वर्गों की हुण्डी द्वारा प्रेषित करता है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की ग है और उसके साथ जमा किए गए मुख्य रूप का पूरा ब्यौरा हम विभाग को भेजना चाहिए।

6. समुद्रपार संचरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इंडिया, टोकियो प्रांच के अन्य खर्च इंडियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्वाचित किए जाएंगे।

7. विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में बैंक के कर्तव्य और जिम्मेदारियां भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए. बी. परिपत्रों में निर्धारित हैं। इस संबंध में विशेष सन्दर्भ ए. बी. परिपत्र सं. 22, दिनांक 18-6-77 का दिया जाता है।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. प्रवर सचिव (टी. ए.) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 198 ITC(PN)/88-91

New Delhi the 31st January, 1990

Subject :—Licensing conditions in respect of Public Section Imports under Japanese Grant Aid of Yen 505.501 million (Y 505.501,000) Debt Relief for 1989-90 extended by the Govt. of Japan.

F. No. IPC/23(28)/85-88.—The term and conditions in respect of Public Section Imports under Japanese Grant Aid of Yen 501.501 million (Y505.501,000) (Debt Relief) for 1989-90, as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

TEJENDRA KHANNA,
Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 198 ITC(PN)/88-91 DATED 31-1-1990

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER JAPANESE GRANT AID OF YEN 505.501 MILLION (Y505, 501,000) (Debt Relief) FOR 1989-90 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN.

Section I—General Conditions

I. (i) The Japanese Grant Aid of Yen 505.501 million extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

(ii) The licence will bear the superscription "Yen 505.501 Million Japanese Grant Aid for 1989-90. The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity period of 12 months. For extension of the validity period of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs, (Japan Section) in the matter.

(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (Japan), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas

supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

(vi) The condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licensing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1991.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

269 GI/90—2

(iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III.

The following provision should be specifically incorporated in the supply contracts :—

III. (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 9-10-89 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 505.501 Million for 1989-90 "and will be subject to the approval of Government of India".

(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' A/P which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Janpath Bhavan, 'B' Wing, 5th Floor, Janpath, New Delhi-110 001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1989-90.

(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after such shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV. Contract Approval by Govt. of India

IV. (i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (Japan) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects with two photocopies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of A/P in the form at Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department

of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of the receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

(v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account. However, in case of Govt. Depts., the banking charges are payable to B.O.I., Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and then debitted to the Depts. concerned.

Section V Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release the negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound sterling payments made to the supplier along with interest charges there on in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83 and No. 35/ITC (PN) 83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The

exchange Pubmputing the rupee equivalent of the Yen/US\$/ Payment will be prevailing composite rate of the exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 113-ITC(PN) 88-91 of 6-4-1989 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advance S-8443 Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 505.501 Million Grant Aid-Debt-Relief). However, no interest is payable by Govt. Deptt.

(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 and No. 113-ITC(PN)/88-91 dated 6-4-1989.

(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that complete information is invariably furnished.

The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(c) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account). However, no interest is payable by Govt. Departments.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section-VI Miscellaneous provisions

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the foreign supplier. Late or delayed receipt of shipping documents etc. by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (ii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1989-90 from Japan.

VI (v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI (vi) List of Annexures :

Annexure-I List of eligible source countries.

Annexure-II List of eligible commodities.

Annexure-III Form of Request for issue of Authorisation to pay (A/P).

Annexure-IV Form of Letter of Authorisation to pay (A/P).

** The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, 'B' Wing, Janpath, New Delhi-110001.

ANNEXURE-I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States.

B Developing Countries & Territories

(b) Non-OPEC Developing Countries

I. Africa North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola
 Botswana
 Burundi
 Camaroon
 Cape Vards Islands
 Central African Rep.
 Chad
 Comoro Islands
 Congo, People's Republic of Dahomay (1)
 Equatorial Guinea
 Ethiopia
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesothe
 Libaria
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritan-ia
 Mauritius
 Moozambique
 Niger
 Portuguese Guinea
 Reunion
 Rhodesia
 Rwanda
 St. Helena and Dep(2)
 Sao Tome and Princpee
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro, Afars and
 Isses
 Tago
 Uganda
 Un. Rep. of Tenazania
 Upper Volta
 Zaire Republic
 Zambia

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinae, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaceessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands, Aruba, Fonaire, Cura ao, Saha, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent

Bahamas
 Barbodosen
 Belize
 Barmuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Maxico
 Netherlands Atilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tabago
 West Indies (Br.) n.e.e.
 (a) Associated States (1)
 (b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Fulkland Islands
 French Guiana
 Guyana
 Paragusy
 Peru
 Surinam
 Uruguary

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Amirates (3)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D. R. (4)

- (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands : Montserrant, Gayman, Turks and Caicos, and British, Virgin Islands.
- (3) IAjman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

VII. ASIA, Far East

Bornei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timer
Vietnam, Rep. of
Vietnam Dam. Rep.

ANNEXURE II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

VIII. Cook Islands

Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Pelynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New B Hebrices (Br. and Fr.)
Hieu
Pecific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

1. Rolls.
2. Steel including special steel & alloy steel.
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks, tractors, light commercial vehicles and two wheel.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas Sector.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

IX. EUROPE

Cyprus

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuametu-Cambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

NO.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid
of Yen 505.501 million for 1989-90.

Sir,

In connection with the import of-
from Japan under the above mentioned Grant Aid,
we furnish the following particulars to enable you to
issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour
of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and address of the Supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (e) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

(q) Indian port to which the equipment/materials are to be shipped.

ANNEXURE IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject: Import under Japanese Debt-Relief Grant
Aid of Yen 505.501 Million—Issue of
Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen——— to M/s.——— (as per details given in the Appendix)

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of the authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should sent to——— (Name & address of importers' Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charge for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importers Bank. However, the banking charges in respect of Govt. Department will be payable to E.O.I., Tokyo by the Embassy of India, Tokyo and debited to the Depts. concerned.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

7. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No. — dated

2. Importers' Banker—

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices/orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) ————— (ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen 1¼ US \$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)/83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance. However, no interest is payable by Govt. Depts.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6

(Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 113 ITC(PN) 88-91 dated 6-4-89 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits(4) & Deposits not having interest Advances 8443-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1989-90 (Yen 505.501 Million Grant Aid-Debt Relief).

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Janpath Bhavan, 'B' Wing, 5th Floor, Janpath, New Delhi-110001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notices issued from time to time, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest at the rate prescribed and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Banks' duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dt. 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (Japan) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to ID No. [Japan dt.

(Accounts Officer)

